बासदेव भारद्वाज-अपीलकर्ता

बनाम

राम सरूप और अन्य,-प्रतिवादी

यूएसए। 1962 का 482

5 जनवरी, 1968

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (1956 का LXXVIII)—एस. 16- वैधानिक अनुमान के तहत - गोद लेने के समर्थन में दिए गए मौखिक साक्ष्य की सत्यता को संदिग्ध माना जाता है - क्या यह ऐसे वैधानिक अनुमान का खंडन करने के बराबर है - साक्ष्य - कब संदिग्ध कहा जा सकता है।

निर्णय, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 16 के तहत , जहां गोद लेने से संबंधित पंजीकृत दस्तावेज है, वहां गोद लेने के पक्ष में धारणा बनाई जाएगी और फिर दूसरे पक्ष को यह साबित करना होगा कि अधिनियम के तहत कोई गोद नहीं लिया गया है। गोद लेने के समर्थन में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एक अतिरिक्त सबूत की प्रकृति में है और यदि न्यायालय इसकी सत्यता पर संदेह करता है, तो वह इसकी उपेक्षा कर सकता है। मौखिक साक्ष्य को संदेह की नजर से देखना अधिनियम की धारा 16 के तहत वैधानिक अनुमान को खारिज करने जैसा नहीं है। किसी साक्ष्य को संदिग्ध तब कहा जाता है जब किसी तथ्य या प्रस्ताव के संबंध में अनिश्चितता मौजूद हो जिसे साबित करने की कोशिश की जा रही हो। संदेह खंडन नहीं है. जब कोई अदालत संदेह में होती है, तो इसका मतलब केवल यह होता है कि अनिश्चितता की स्थिति है। 'संदिग्ध* शब्द न्यायालय की मनःस्थिति को दर्शाता है कि कोई विशेष साक्ष्य या तथ्य स्थापित है या नहीं। संदिग्ध मौखिक साक्ष्य की अस्वीकृति कानूनी अनुमान के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकती है जो क़ानून गोद लेने के पंजीकृत विलेख के निष्पादन से जुड़ा हुआ है। फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबंस के बीच अंतर को ध्यान में रखना होगा।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव कैम्प रोहताल की अदालत की डिक्री, दिनांक 20 फरवरी 1962, के खिलाफ दूसरी अपील, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, रोहताली की अदालत की डिक्री, दिनांक 29 मई, 1961 को पलटते हुए और उसे मंजूर करते हुए वादी ने एक डिक्री के रूप में प्रतिवादी के विरुद्ध लागत सहित वाद भूमि पर कब्ज़ा करने की प्रार्थना की।

टेक चंद, जे.-इस नियमित दूसरी अपील में उठने वाले बिंदुओं की सराहना करने के लिए, पार्टियों के बीच मुकदमेबाजी का पिछला इतिहास देना आवश्यक है। रामजी लाई, जिनकी संपत्ति इस मुकदमे का विषय है, की 1925 में मृत्यु हो गई। उनके बेटे हर फूल की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। रामजी लाई की मृत्यु पर, अपीलकर्ता बासदेव के पक्ष में उत्परिवर्तन को इस आधार पर मंजूरी दी गई थी कि वह रामजी लाई के पूर्व-मृत पुत्र हर फूल का पुत्र था। छब्बीस की संख्या में वादी, जो रामजी लाई के आठवें डिग्री के सहयोगी थे, ने यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि बासदेव रामजी लाई के पोते नहीं थे और इसलिए, उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के हकदार नहीं थे। उन्होंने संपत्ति पर कब्ज़ा मांगा। मुकदमे का फैसला सुनाया गया और परिणामस्वरूप राजस्व अधिकारियों ने वादी के नाम पर उत्परिवर्तन को मंजूरी दे दी।

1927 में एक और मुकदमा शुरू हुआ, रामजी लाई की बेटी किशन देवी ने इस आधार पर वादी पर कब्ज़ा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि रामजी लाई की संपत्ति गैर-पैतृक थी। उनके मुकदमे पर 11 दिसंबर, 1928 को फैसला सुनाया गया और फैसला उच्च न्यायालय तक बरकरार रखा गया। डिक्री के अनुपालन में किशन देवी ने कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद, किशन देवी ने इस जमीन को गंगा राम के पक्ष में गिरवी रख दिया और उसने अपने गिरवीदार अधिकार को बासदेव के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया। 20 जुलाई, 1937 को किशन देवी ने अपनी सारी संपत्ति बासदेव के पक्ष में दान कर दी। बंधक और उपहार को वादी द्वारा चुनौती दी गई थी और उनके मुकदमे पर 21 दिसंबर, 1940 को फैसला सुनाया गया था। यह माना गया था कि किशन देवी का केवल जीवन भर का हित था और उनकी मृत्यु के बाद, विवादित उपहार और बंधक वादी के प्रत्यावर्ती अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगे। .

मुकदमेबाजी का अगला चरण यह है कि किशन देवी ने बासदेव के बेटे मुकेश कुमार को अपने बेटे के रूप में गोद लिया और गोद लेने का एक पंजीकृत दस्तावेज 11 जुलाई, 1957 को निष्पादित किया गया, जो गोद लेने की तारीख भी है। 3 जनवरी 1960 को किशन देवी की मृत्यु हो गई।

14 अप्रैल, 1960 को, वर्तमान मुकदमा जिसमें से दूसरी अपील उत्पन्न हुई है, वादी द्वारा 21 दिसंबर, 1940 को उनके पक्ष में पारित घोषणात्मक डिक्री के आधार पर संपत्ति के कब्जे के लिए शुरू किया गया था। मुकेश कुमार को इन कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

इस मुकदमे में बासदेव का बचाव यह है कि घोषणात्मक डिक्री बाध्यकारी नहीं थी क्योंकि पूर्व मुकदमा जिसके परिणामस्वरूप डिक्री हुई थी, उसके अभिभावक द्वारा ठीक से संचालित नहीं किया गया था। वह नाबालिग था.

उनका दूसरा बचाव यह है कि किशन देवी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के मद्देनजर मुकदमे में संपत्ति की पूर्ण मालिक थीं। तीसरा, यह तर्क दिया गया कि किशन देवी ने मुकेश कुमार को गोद लिया था और वादी के पक्ष में कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी क्योंकि वे अब अधिमान्य उत्तराधिकारी नहीं थे। अंत में, यह आग्रह किया गया कि मुकेश कुमार एक आवश्यक पक्ष थे और उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता।

वादी ने अपनी प्रतिकृति में कहा कि मुकेश कुमार को गोद लेने से पहले, किशन देवी ने एक आसा राम को गोद लिया था और इसलिए, मुकेश कुमार को बाद में गोद लेना वैध नहीं था। उपरोक्त दलीलों पर, ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए:—•

(1) क्या वादी द्वारा प्राप्त घोषणात्मक डिक्री, दिनांक 21 दिसंबर, 1940, लिखित बयानों के पैरा 4, 5 में दिए गए कारणों से प्रतिवादी बासदेव पर बाध्यकारी नहीं है? यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या होगा?

(2) क्या एम.एस.टी. किशन देवी ने वैध रूप से मुकेश कुमार को गोद लिया था? यदि हां, तो वर्तमान मुकदमे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? (मुकेश कुमार को गोद लेने की योग्यता शामिल की जा रही है

. इस अंक में।)

(3) यदि उपरोक्त वाद क्रमांक 2 सिद्ध हो तो क्या मुकेश कुमार वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

वी

(4) 21 दिसंबर 1940 की डिक्री पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का क्या प्रभाव है?

(5) क्या एम.एस.टी. किशन देवी ने पहले एक आसा राम को गोद लिया था? यदि हां, तो इसका मुकेश को गोद लेने और वर्तमान मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(6) राहत.

ट्रायल कोर्ट ने पहले मुद्दे पर कहा कि घोषणापत्र। डिक्री बाध्यकारी थी लेकिन मुकेश कुमार को किशन देवी ने वैध रूप से गोद ले लिया था। यह भी माना गया कि मुकेश कुमार एक आवश्यक पक्ष थे। चौथे मुद्दे पर, यह माना गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 का लाभ किशन देवी को नहीं मिल सका और 21 दिसंबर, 1940 को पारित डिक्री अप्रभावित रही। पाँचवें मुद्दे पर आसा राम के पिछले गोद लेने का निर्णय लिया गया वादी के विरुद्ध. वादी का मुकदमा लागत सहित ख़ारिज कर दिया गया। वादी ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के समक्ष अपील की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और जहां से बासदेव ने यह दूसरी अपील प्रस्तुत की है।

दूसरी अपील में जिन बिंदुओं पर विवाद किया गया है, वे गोद लेने के तथ्य की वैधता से संबंधित हैं। निचली अपीलीय टी

अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अनुमान, यदि कोई हो, * से उत्पन्न होता है

गोद लेने के समर्थन में पंजीकृत दस्तावेज़ को पर्याप्त रूप से खंडन किया गया माना जाना चाहिए और गोद लेने का निर्णय स्थापित नहीं किया गया था। हालाँकि, यह देखा गया कि यद्यपि वादी 1940 में प्राप्त घोषणात्मक डिक्री के आधार पर मुकदमे की भूमि के संबंध में स्वामित्व राहत के हकदार थे, लेकिन नाबालिग मुकेश कुमार के अधिकार जो एक आवश्यक पक्ष थे और जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था अप्रभावित रहेगा; और विवादित भूमि में उसके हित, यदि कोई हो, पर अदालत की किसी भी टिप्पणी से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गोद लेने के हिंदू कानून को संहिताबद्ध किया गया है और कानून में भौतिक परिवर्तन किए गए हैं। धारा 8 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक हिंदू महिला अब बेटे या बेटी को गोद लेने की क्षमता रखती है। यह एक दूरगामी परिवर्तन है और सख्त हिंदू कानून से हटकर है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 16 है, जो गोद लेने से संबंधित पंजीकृत दस्तावेजों के बारे में धारणाओं के संबंध में है और इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"जब भी किसी भी कानून के तहत पंजीकृत किसी भी दस्तावेज़ को गोद लेने के रिकॉर्ड के लिए किसी भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उस पर गोद लेने वाले व्यक्ति और बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, तो अदालत यह मान लेगी कि गोद लेना इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में बनाया गया है जब तक कि इसे अस्वीकृत नहीं किया जाता है।

इस प्रावधान का महत्व यह है कि एक बार गोद लेने का पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित हो जाने के बाद, "अदालत यह मान लेगी" कि गोद लेना अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में है "जब तक कि यह अस्वीकृत न हो जाए"। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के तहत, शब्द "धारणा करेगा" का अर्थ यह समझा जाता है कि अदालत किसी तथ्य को मान लेगी और ऐसे तथ्य को साबित मानेगी जब तक कि वह अस्वीकृत न हो जाए: -

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत, किसी तथ्य को तब अस्वीकृत कहा जाता है, जब पहले के मामलों पर विचार करने के बाद

यह, न्यायालय या तो मानता है कि इसका अस्तित्व नहीं है, या इसके गैर-अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि एक विवेकशील व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि इसका अस्तित्व नहीं है।

इस प्रकार, जहां गोद लेने से संबंधित एक पंजीकृत दस्तावेज है, वहां गोद लेने के पक्ष में धारणा बनाई जाएगी और फिर दूसरे पक्ष को यह साबित करना होगा कि अधिनियम के तहत कोई गोद नहीं लिया गया है। प्रदर्शनी डी/3, रामजी लाई की बेटी श्रीमती किशन देवी द्वारा 11 जुलाई, 1957 को निष्पादित गोद लेने का मूल विलेख है। इस पर उनके अंगूठे का निशान है। प्रदर्शनी डी/3 में गोद लेने वाले व्यक्ति के रूप में बासदेव के "भगवान के पीछे" के रूप में हस्ताक्षर हैं। इसे कई गवाहों और मुंशी द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। विलेख में कहा गया है कि किशन देवी एक विधवा है, उसकी उम्र अस्सी वर्ष है और उसे पुरुष या महिला संबंधी कोई समस्या नहीं है। वह आम तौर पर बासदेव और उनके पांच साल के बेटे मुकेश कुमार के घर में रहती है, जिससे उसे बहुत स्नेह है और जो उसके बेटे के रूप में उसके साथ रहता है और उसने उसे गोद में ले लिया है; उन्होंने ऐसा हवन, पूजा, मिठाइयां बांटने और तस्वीर लेने जैसे पारंपरिक अनुष्ठान करने के बाद किया है; कि बासदेव ने अपने बेटे मुकेश कुमार को किशन देवी द्वारा गोद लेने पर सहमति दे दी है। जब मुकेश कुमार को उसकी गोद में बिठाया जा रहा था तब मौजूद लोगों की एक तस्वीर रिकॉर्ड में पेश की गई है। प्रदर्शनी डी/4, बासदेव द्वारा अपने बेटे मुकेश कुमार को सोनीपत के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए 18 अप्रैल, 1958 को दिए गए आवेदन की एक प्रति है। पिता के नाम के कॉलम में "बलदेव दत्तक पुत्र एमएसटी" लिखा हुआ है। किशन देवी" मुकेश कुमार की जन्म तिथि 4 मार्च, 1953 बताई गई है। प्रतिवादी ने गोद लेने के तथ्य के सबूत में आठ गवाह पेश किए हैं। वादी पक्ष के नेतृत्व में गोद लेने के सबूत को खारिज करने वाला कोई सबूत नहीं है और निचली अपीलीय अदालत ने किसी का उल्लेख नहीं किया है। गोद लेने के पंजीकृत विलेख के निष्पादन के लगभग दो साल और छह महीने बाद, गोद लेने वाली किशन देवी की 3 जनवरी, 1960 को मृत्यु हो गई।

अपीलकर्ता बासदेव के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 16 के प्रावधानों के मद्देनजर, गोद लेने के पक्ष में एक धारणा थी और जब तक यह धारणा साक्ष्य द्वारा अस्वीकृत नहीं हो जाती, तब तक धारणा निस्तारण किया हुआ नहीं माना जा सकता। एक बार गोद लेने का वैध रूप से निष्पादित विलेख स्थापित हो जाने के बाद, वैध गोद लेने के पक्ष में अनुमान लगाना अदालत के लिए कानूनन अनिवार्य था।

जब तक कि विपरीत पक्ष ने इसे अस्वीकृत करने की ज़िम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। यह भी तर्क दिया गया कि निचली अपीलीय अदालत ने रिकॉर्ड पर रखे गए मौखिक साक्ष्यों की सत्यता पर ग़लती से संदेह और संदेह व्यक्त किया था। भले ही साक्ष्य संदिग्ध विश्वसनीयता का था, इसे नजरअंदाज कर दिया गया होगा, लेकिन यह आवश्यक रूप से धारा टी 16 के तहत अपनाने या अनुमान का खंडन करने के बराबर नहीं होगा। यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी अपीलकर्ता के नेतृत्व में मौखिक साक्ष्य की अस्वीकृति नहीं होगी। कानूनी अनुमान को गलत साबित करने के लिए। मौखिक साक्ष्य एक अतिरिक्त सबूत की प्रकृति में था और यदि निचली अपीलीय अदालत इसकी सत्यता पर संदेह करती है, तो वह इसकी उपेक्षा कर सकती है। प्रतिवादी अपीलकर्ता के मौखिक साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से देखना धारा 16 के तहत वैधानिक अनुमान को अस्वीकार करने जैसा नहीं है। एक साक्ष्य को संदिग्ध तब कहा जाता है जब किसी तथ्य या प्रस्ताव के संबंध में अनिश्चितता मौजूद होती है जिसे साबित करने की मांग की जाती है। संदेह खंडन नहीं है. जब कोई अदालत संदेह में होती है, तो इसका मतलब केवल यह होता है कि अनिश्चितता की स्थिति है। 'संदिग्ध' शब्द न्यायालय की मनःस्थिति को दर्शाता है कि कोई विशेष साक्ष्य या तथ्य स्थापित है या नहीं। संदिग्ध मौखिक साक्ष्य की अस्वीकृति कानूनी अनुमान के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकती है जो क़ानून गोद लेने के पंजीकृत विलेख के निष्पादन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में मौखिक साक्ष्य पर संदेह जताना अभी भी अधिनियम की धारा 16 के तहत कानूनी अनुमान को बरकरार रखता है। भले ही प्रतिवादी अपीलकर्ता द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया गया हो, अदालत को वैध गोद लेने के पक्ष में अनुमान लगाना आवश्यक था। इस अनुमान को वादी पक्ष द्वारा खंडन में ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करके अस्वीकृत किया जाना था। वादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार कानूनी धारणा अप्रभावित रहती है और उसका खंडन नहीं किया जाता है। निचली अपीलीय अदालत ने इस प्रकार कानून के तहत मामले से निपटने में कानून में गलती की है क्योंकि यह अधिनियम के लागू होने से पहले मौजूद था और वैध गोद लेने के पक्ष में कानूनी अनुमान के प्रभाव को गलत समझा।

फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबंस के बीच अंतर को ध्यान में रखना होगा। तथ्यात्मक जांच या इस मामले में साबित किया जाने वाला तथ्य यह है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक पंजीकृत दस्तावेज जे पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य गोद लिए गए बच्चे को रिकॉर्ड करना था और उस पर बच्चे को गोद लेने वाले और देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इन तथ्यात्मक जांचों पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। पंजीकरण विलेख में किशन देवी द्वारा मुकेश कुमार को गोद लेने का रिकॉर्ड है। बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति के रूप में उसके अंगूठे का निशान, और गोद लेने वाले व्यक्ति (भगवान देहिन्दा) के रूप में बासदेव के हस्ताक्षर विलेख पर अंकित हैं।

प्रमाणित करने वाले गवाहों ने विलेख के निष्पादन के लिए गवाही दी है। इस तरह के दस्तावेज़ के प्रस्तुत होने के बाद, धारा 16 के लिए आवश्यक है कि अदालत यह मान ले कि गोद लेना अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में किया गया है जब तक कि यह अस्वीकृत न हो जाए। जो कुछ कहा गया है वह यह है कि बासदेव ने दस्तावेज़ पर एक प्रमाणित गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं न कि एक निष्पादक के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है। यह इंगित करने के अलावा कि वह देहिन्दा का देवता था, उसने अपने नाम पर 'अलब्द' (हस्ताक्षर या नुस्खे, न कि 'गवा शुद्ध' (साक्षी) के तहत हस्ताक्षर किए हैं। मेरे विचार में, धारा 16 की आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं। वहाँ है अदालत के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, और यह तथ्य को साबित मानने के लिए बाध्य है, जब तक कि इसे अस्वीकार करने के लिए सबूत नहीं दिए जाते हैं और इसे खारिज करने में रुचि रखने वाले पक्ष को यदि संभव हो तो ऐसे सबूत पेश करने होंगे। तथ्यात्मक जांच यह थी कि गोद ले लिया गया था इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। मौखिक साक्ष्य की विश्वसनीयता पर दोषारोपण करके अनुमानित प्रमाण को अस्वीकार करने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए कि यह सफलतापूर्वक किया गया था, तो यह केवल यह साबित करेगा कि गवाहों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा अनुमान को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सच है कि अनुमान एक अनुमान

न्यायशास्त्र है और यह एक पक्ष को यह दिखाने के लिए सक्षम है कि अनुमान गलत था। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि धारा 16 एक अनुमान न्यायशास्त्र और कानूनी रूप से नहीं उठाती है जब नहीं अनुमान को विस्थापित करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति है। मुकदमे पर फैसला सुनाते समय, ट्रायल कोर्ट ने कुछ परिस्थितियों पर भरोसा किया है।

निचली अपीलीय अदालत ने कहा था कि यह लेन-देन संदेहास्पद है क्योंकि पिछले दो मौकों पर रामजी लाल द्वारा छोड़ी गई जमीन पर दावा करने के लिए प्रतिवादी बासदेव द्वारा या उसकी ओर से असफल प्रयास किया गया था। यह सच है कि बासदेव पिछले दो प्रयासों में असफल रहे थे, लेकिन इस अवसर पर, परिस्थितियाँ पूरी तरह से उनके पक्ष में बदल गई थीं, जहाँ तक कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 को संसद द्वारा पारंपरिक हिंदू कानून में भारी बदलाव करके अधिनियमित किया गया था। गोद लेना। हिंदू महिला को गोद लेने की शक्ति दी गई। इस परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि किशन देवी गोद लेने के कानून की संहिता का लाभ उठाकर मुकेश कुमार को गोद लेने में सक्षम हो गई। बासदेव द्वारा अपने बेटे को किश देवी को गोद देने में कुछ भी अवैध नहीं किया गया था जब तक कि वह जानती थी कि वह क्या कर रही थी और उसने ऐसा किया। कानून ने उसे बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया था। दूसरी परिस्थिति यह है कि वह अस्सी वर्ष की महिला थी और इस उम्र में उसे बच्चे से कोई प्रयोजन नहीं था। यह भी कहा गया कि 1915-1916 में वह विधवा हो गईं और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था

पहले अपनाने का. गोद लेने का अधिकार उन्हें 1956 में अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। पहले, एक विधवा को अपने पति को गोद लेने का अधिकार था, बशर्ते कि पति ने उसे यह इच्छा बताई हो। कुछ मामलों में, वह ऐसी चोट के बावजूद ऐसा कर सकती थी; उसके पति की हरकतें. लेकिन अगर मान लिया जाए कि एक विधवा ने अस्सी साल की हो जाने पर एक बच्चे को गोद लेने की सोची, तो किसी भी कानून ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। कानून किसी पंजीकृत दस्तावेज़ को जो पवित्रता देता है, उसे इस संदेह से दूर नहीं किया जा सकता कि वह इस तरह के दस्तावेज़ को निष्पादित करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि रजिस्ट्रार का समर्थन झूठा है। तब यह कहा गया कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं बची है और ऐसे बेटे को गोद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके लिए वह कुछ भी नहीं छोड़ सकती। लेकिन गोद लेने का कार्य इस बात से स्वतंत्र है कि गोद लेने वाले के पास कोई संपत्ति है या नहीं।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तब आग्रह किया, कि जब निचली अपीलीय अदालत देने और लेने के समारोह के प्रदर्शन के संबंध में "मुझे संदेह है" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है, तो इसे "मुझे संदेह है" के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि गोद लेना अस्वीकृत है. निचली अपीलीय अदालत गवाहों द्वारा बताई गई कुछ घटनाओं के बारे में संदेह पर विचार कर सकती है, लेकिन यह पंजीकृत विलेख में कही गई बातों को खारिज करने के समान नहीं होगा। फिर, यह कहा गया कि बच्चा छुट्टियों के अलावा उसके गांव में उसके साथ नहीं रहता था और यह परिस्थिति गोद लेने के तथ्य से अलग थी। एक बार जब गोद ले लिया जाता है और यह तथ्य एक पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा प्रमाणित हो जाता है, तो बच्चे का गोद लेने वाली माँ के साथ गाँव में न रहना ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जिससे कानूनी धारणा का खंडन किया जा सके।

विल्स ने अपनी पुस्तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सातवें संस्करण में पृष्ठ 296-297 पर लिखा है:

'नैतिक जांच में तथ्य आमतौर पर तब अधिक अस्पष्ट रूप से विकसित होते हैं जब भौतिक घटनाएं जांच का विषय बनती हैं; और उन्हें अक्सर विदेशी और अप्रासंगिक परिस्थितियों के साथ मिश्रित किया जाता है, जिससे तथ्यात्मक प्रोबैंडम के साथ उनका संबंध स्थापित करना काफी कठिनाई का विषय बन जाता है। इसलिए, उन परिस्थितियों पर कोई भार नहीं डाला जाना चाहिए, जो हालांकि, अनुमान को उत्तेजित कर सकती हैं, विश्वास की गारंटी नहीं देती हैं। घटनाएँ रहस्यमय हो सकती हैं और प्रबल संदेह को भी उचित ठहरा सकती हैं, और फिर भी कल्पित को

उनके बीच संबंध काल्पनिक हो सकता है, और उनका सह-अस्तित्व केवल आकस्मिक सहमति का सूचक है, न कि आपसी सहसंबंध का।''

सह - संबंध।"

अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री जे.एन. कौशल ने आग्रह किया कि निचली अपीलीय अदालत ने साक्ष्यों पर विचार करते समय कानून संबंधी त्रुटियां की हैं। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दल बहादुर सिंह और अन्य बनाम बिजय बहादुर सिंह और अन्य (1) के आधार पर कहा कि जिस गोद लेने से संपत्ति का प्राकृतिक उत्तराधिकार बाधित होता है, उसे सख्त और मजबूत सबूतों से साबित किया जाना चाहिए, और उन्होंने सोचा , कि गोद लेने के किसी दिए गए मामले में सबूत के लिए सख्त और लगभग गंभीर जांच की आवश्यकता होती है। धारा 16 के अनुसार तैयार की जाने वाली कानूनी धारणा के सामने, उपरोक्त सिद्धांत अच्छा नहीं है। मामले का निर्णय प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित पुराने कानून के आधार पर नहीं, बल्कि नए अधिनियम द्वारा संहिताबद्ध कानून के आधार पर किया जाना था। निचली अपीलीय अदालत द्वारा अनुमोदित अगला प्रस्ताव यह था कि एक अनपढ़ व्यक्ति के मामले में गोद लेने के विलेख का निष्पादन और पंजीकरण केवल गोद लेने के पर्याप्त सबूत की आपूर्ति के रूप में माना जा सकता है। यह प्रस्ताव पूरी तरह से गलत है और धारा 16 के विपरीत है। पंजीकृत दस्तावेज़ से जुड़ी पवित्रता से संबंधित कानून साक्षर या अशिक्षित निष्पादकों के बीच अंतर नहीं करता है।

निचली अपीलीय अदालत ने तब देखा कि गोद लेने के विलेख को गोद लेने वाले की मृत्यु से बहुत कम समय पहले निष्पादित किया गया था और उस परिस्थिति को बड़े संदेह के साथ देखा जाना चाहिए और आगे कहा कि अदालतों ने हमेशा ऐसे विलेख को सबूत के रूप में मानने से इनकार कर दिया है। अपनाने का इरादा. यह प्रस्ताव भी उतना ही ग़लत है और जैसा कि कहा गया है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हालाँकि, इस मामले में, तथ्य यह है कि गोद लेने के दस्तावेज के निष्पादन और किशन देवी की मृत्यु के बीच ढाई साल का अंतराल था। तब कहा गया था कि इन परिस्थितियों में किशन देवी पर कोई अनुचित प्रभाव डाला गया होगा। यह निष्कर्ष किसी भी तथ्य से समर्थित नहीं है. यह संभव है कि वह महिला जो बूढ़ी थी और उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था जो वैध रूप से उसके इनाम का विषय हो सकता था। यह एक बात है कि बासदेव ने उसे अपने बच्चे को गोद लेने के लिए राजी किया होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने बच्चे को गोद लेने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की, या उस पर अनुचित प्रभाव डाला, खासकर जब वह पहले से ही एक उपहार दे चुकी थी और घाटे में थी। या के कार्य को निष्पादित करके कुछ भी हासिल नहीं करें

(1) ए.आई.आर., 1930 पी.सी. 79.

दत्तक ग्रहण। अनुचित प्रभाव के किसी भी सबूत के अभाव में, उस पर कोई दबाव डालने के पक्ष में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

निचली अपीलीय अदालत ने केवल इतना कहा कि इसे "ख़ारिज नहीं किया जा सकता"। मामले को या तो सकारात्मक रूप से या उचित संभावना के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। किसी अनुमान को खारिज करने की क्षमता अनुचित प्रभाव के उपयोग के प्रमाण के समान नहीं है। मेरे विचार से, जिन परिस्थितियों पर निचली अपीलीय अदालत ने सीखा है, वे धारा 16 के तहत कानूनी अनुमान प्रदर्शित करने के लिए कानून में पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ तथ्यात्मक आकस्मिकताओं के बारे में भी निचली अपीलीय अदालत के निष्कर्ष कानून की त्रुटियों से दूषित हैं। निचली अपीलीय अदालत के अधिकांश निष्कर्ष दूषित हैं क्योंकि वे अनुमान की प्रकृति के हैं जो तथ्य के आधार के बिना अनुमान हैं। अनुमान एक विचार या धारणा है जो बिना किसी सत्यता के प्रदर्शन के संभाव्यता पर आधारित होती है। निष्कर्ष कुछ संभावित तथ्यों पर आधारित अनुमान हैं जिनका कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं है। ये स्पष्टीकरण की प्रकृति के अनुरूप हैं, लेकिन ज्ञात तथ्यों या स्थितियों से उचित निष्कर्ष के रूप में अनुमान लगाने योग्य नहीं हैं।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने धीरजलाल गिरधारीलाल बनाम कॉमरेड का हवाला दिया। आयकर विभाग, बॉम्बे (2), जिसमें यह देखा गया कि यदि तथ्य न्यायालय जिसका तथ्य का निर्णय अंतिम है, उस सामग्री पर विचार करके तथ्य के निर्णय पर पहुंचा जो जांच के लिए अप्रासंगिक है, या उस सामग्री पर विचार करके जो आंशिक रूप से प्रासंगिक और आंशिक रूप से अप्रासंगिक है, या अपने निर्णय को आंशिक रूप से अनुमानों, अनुमानों और संदेहों और आंशिक रूप से साक्ष्यों पर आधारित करता है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से कानून का मुद्दा उठता है। तथ्य की ऐसी खोज अस्वीकार्य सामग्री के उपयोग के कारण दूषित हो जाती है और इस प्रकार कानून का मुद्दा उठता है।

श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, मदुरै बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास (3) में, पृष्ठ 65 पर यह देखा गया कि तथ्य के प्रश्न पर एक निष्कर्ष कानून में गलत होने के रूप में हमला करने के लिए खुला था जब समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था यह या यदि यह विकृत था.

' *■*

वी. रामचन्द्र अय्यर और अन्य बनाम रामालिंगम चेट्टियार और अन्य (4) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि

(2) ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 271

(3) ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 49.

(4) ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 302,

राम दित्ता सिंह बनाम उपायुक्त, फ़िरोज़पुर, आदि

यदि तथ्य के प्रश्न से निपटने में, निचली अपीलीय अदालत ने गलत पक्ष पर जिम्मेदारी डाल दी है और तथ्य की खोज काफी हद तक इस गलत दृष्टिकोण का परिणाम है, तो इसे प्रक्रिया में दोष माना जा सकता है।

निचली अपीलीय अदालत में जो विचार किए गए, वे उपरोक्त अर्थों में अनुमानित थे, उदाहरण के लिए, तथ्य यह है कि बासदेव ने एक बार खुद को रामजी लाई का भव्य पुत्र होने का दावा किया था, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं पाया और इसलिए , यह माना जाना चाहिए था कि गोद लेना एक प्रहसन की प्रकृति में था। इसी तरह, निचली अपीलीय अदालत इस परिस्थिति से प्रभावित थी कि अस्सी साल की महिला के पास बच्चे को गोद लेने का कोई कारण नहीं था और इसे यह मानने के लिए एक आधार के रूप में माना जाना चाहिए था कि वास्तव में गोद लेने में कोई लेना-देना नहीं था। एक और विचार यह था कि यदि वह अपने पति की इच्छा के अनुसार एक बच्चा गोद लेना चाहती थी, तो उसने ऐसा पहले ही कर लिया होता क्योंकि वह 1915 या 1916 में किसी समय विधवा हो गई थी।

"इस मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह कभी भी आरोप नहीं लगाया गया था कि पंजीकरण फर्जी था और एक बार गोद लेने का एक पंजीकृत विलेख है और पंजीकरण के तथ्य पर संदेह नहीं किया गया है, जो अस्वीकार करने के लिए खुला है वह इसका अनुपालन न करना है अधिनियम के प्रावधान। निचली अपीलीय अदालत द्वारा विचार की गई परिस्थितियाँ उस धारणा को विस्थापित नहीं करती हैं जिसे अधिनियम की धारा 16 के तहत उठाया जाना है।

मैं संतुष्ट हूं कि निचली अपीलीय अदालत ने धारा 16 की धारणा की उपेक्षा की और ऐसा करके कानून की गलती की। मैं अपील की अनुमति दूंगा, निचली अपीलीय अदालत की डिक्री को रद्द कर दूंगा और ट्रायल कोर्ट की डिक्री की पुष्टि करूंगा। प्रतिवादी अपीलकर्ता संपूर्ण लागत का हकदार होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र